Toppersnotes®
Unleash the topper in you

मध्य प्रदेश

सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor)

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)

वाणिज्य

भाग - 1

SIERRA INNOVATIONS

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
	इकाई - I : व्यवसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय	
1.	व्यवसाय परिवेश की संकल्पना एवं तत्व (Concepts and Elements of Business Environment)	1
2.	अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र एवं महत्व (Scope and Importance of International Business)	3
3.	अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत (Theories of International Trade)	4
4.	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)	6
5.	अंतरराष्ट्रीय भुगतान संतुलन (Balance of Payments - BoP)	9
6.	क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण (Regional Economic Integration)	11
7.	4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ (4 Major International Economic Institutions)	12
8.	विश्व व्यापार संगठन (WTO - World Trade Organization)	15
9.	मौद्रिक नीति (Monetary Policy)	17
10.	राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)	18
11.	विश्व बैंक (World Bank)	20
12.	IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष)	21
13.	नई आर्थिक नीति 1991 (New Economic Policy 1991)	23
14.	Previous Year Questions	27
	इकाई - II : लेखांकन और अंकेक्षण	
1.	लेखांकन और अंकेक्षण	38
2.	लेखांकन परंपराएँ क्या हैं?	43
3.	साझेदारी (Partnership)	49
4.	प्रमुख लेखांकन बिंदु (Important Accounting Aspects)	53
5.	नए साझेदार का प्रवेश (Admission of a New Partner)	55
6.	सहायक कंपनी की लेखांकन प्रणाली (Accounting of Subsidiary Company)	81
7.	अंकेक्षण : एक परिचय	96
8.	Audit	120
9.	Types of Audit Working Paper	127
10.	Company act	133
11.	Section 141 – Eligibility, Qualifications and Disqualifications of Auditors	136
12.	Section 142 – Remuneration of Auditors	138
13.	Section 143 – Powers and Duties of Auditors and Auditing Standards	139
14.	Section 144 – Auditor के प्रतिबंधित कार्य (Prohibited Services by Auditor)	141
15.	Section 145 – Signing of Audit Report	143
16.	Section 146 – Auditor to Attend General Meeting	144
17.	Section 147 – Punishment for Contravention	145
18.	Section 148 – Cost Audit (लागत लेखा परीक्षा)	146
19.	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (IFRS)	148
20.	Value Added Statement मूल्यवर्धन लेखांकन	158
21.	Human Resource Accounting	162
22.	Previous Year Questions	164

I UNIT	# व्यवसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय

व्यवसाय परिवेश की संकल्पना एवं तत्व (Concepts and Elements of Business Environment)

1. व्यवसाय परिवेश की संकल्पना (Concept of Business Environment):

परिभाषा (Definition):

- व्यवसाय परिवेश उन सभी बाहरी एवं आंतरिक शक्तियों, परिस्थितियों और संस्थाओं का समूह है, जो किसी व्यवसाय के संचालन, निर्णयों, रणनीतियों और प्रदर्शन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं।

आसान शब्दों में:

- व्यवसाय के चारों ओर जो भी घटक होते हैं – जैसे सरकार की नीति, उपभोक्ता की पसंद, प्रौद्योगिकी, समाज – यह सब मिलकर व्यवसाय का परिवेश बनाते हैं।

2. व्यवसाय परिवेश की विशेषताएँ (Features of Business Environment):

(1) परिवर्तनशीलता (Dynamic Nature): यह समय-समय पर बदलता रहता है (जैसे: GST लागू होना)।

(2) जटिलता (Complexity): यह विभिन्न घटकों से बना होता है, जो एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

(3) अवश्यंभाविता (Uncertainty): राजनीतिक, आर्थिक या तकनीकी बदलाव अचानक हो सकते हैं।

(4) परस्पर निर्भरता (Interdependence): विभिन्न तत्व एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं।

(5) सापेक्षता (Relativity): एक ही घटना अलग-अलग देशों या उद्योगों के लिए अलग प्रभाव डाल सकती है।

3. व्यवसाय परिवेश के तत्व (Elements of Business Environment):

- व्यवसाय परिवेश को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है:

A. आंतरिक परिवेश (Internal Environment):

- ✓ वह घटक जो संगठन के नियंत्रण में होते हैं।
- ✓ इनका प्रभाव सीधे व्यवसाय की रणनीति, निर्णय और संस्कृति पर पड़ता है।

- **मुख्य घटक:**
  1. कंपनी की संस्कृति एवं मूल्य (Organizational Culture & Values)
  2. प्रबंधन और कर्मचारी (Management & Employees)
  3. संगठनात्मक संरचना (Organizational Structure)
  4. वित्तीय संसाधन (Financial Resources)
  5. उत्पादन क्षमता और तकनीक (Production & Technology)

B. बाहरी परिवेश (External Environment):

- वे तत्व जो संगठन के बाहर होते हैं और जिन पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता लेकिन प्रभाव अवश्य होता है
- इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है:

1. सूक्ष्म (Micro) परिवेश:

- ये तत्व सीधे व्यवसाय के रोज़मर्रा के संचालन को प्रभावित करते हैं। इन्हें “कार्यशील वातावरण” भी कहा जाता है।

घटक:

घटक	विवरण
ग्राहक (Customers)	व्यवसाय की सफलता का आधार
प्रतिस्पर्धी (Competitors)	बाज़ार में प्रतिस्पर्धा और रणनीति निर्धारण
आपूर्तिकर्ता (Suppliers)	कच्चे माल और सेवाओं की निरंतर आपूर्ति
बिचौलिये/वितरक (Intermediaries)	उत्पाद को अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने में मदद
सार्वजनिक समूह (Public)	मीडिया, एनजीओ आदि जो ब्रांड छवि को प्रभावित कर सकते हैं

2. व्यापक (Macro) परिवेश:

- ये दूरस्थ वातावरण के तत्व हैं जो पूरे उद्योग या देश को प्रभावित करते हैं।
- इन्हें "सामान्य वातावरण" भी कहा जाता है।
- **घटक (PESTEL मॉडल के आधार पर):**

घटक	विस्तृत विवरण
राजनीतिक (Political)	सरकार की नीति, स्थिरता, कर नीतियाँ
आर्थिक (Economic)	मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, GDP, रोजगार दर
सामाजिक-सांस्कृतिक (Socio-Cultural)	उपभोक्ता की जीवनशैली, शिक्षा स्तर, मूल्य
प्रौद्योगिकीय (Technological)	नई तकनीक, R&D, स्वचालन
पर्यावरणीय (Environmental)	जलवायु, हरित नियम, कार्बन नीति
कानूनी (Legal)	श्रम कानून, उपभोक्ता सुरक्षा कानून, औद्योगिक नीतियाँ

4. व्यवसाय परिवेश का महत्व (Importance of Business Environment):

(1) अवसरों और खतरों की पहचान में सहायक
(2) रणनीतिक योजना बनाने में सहायक
(3) प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करने में मददगार
(4) नवाचार और अनुकूलन को प्रेरित करता है
(5) दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित करता है

5. **व्यवसाय परिवेश का विश्लेषण उपकरण (Tools for Environment Analysis):**

उपकरण	उद्देश्य
SWOT Analysis	Strength, Weakness, Opportunity, Threats की पहचान
PESTEL Analysis	मैक्रो फैक्टर्स का विश्लेषण
Porter's Five Forces	उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का मूल्यांकन
ETOP (Environmental Threat and Opportunity Profile)	अवसरों और खतरों की प्रोफाइलिंग

निष्कर्ष (Conclusion):

व्यवसाय परिवेश को समझना और उसका विश्लेषण करना प्रत्येक व्यवसाय संगठन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह उसे बदलते बाह्य व आंतरिक कारकों के अनुरूप रणनीति बनाने में सक्षम बनाता है। यह न केवल जोखिम कम करता है, बल्कि विकास के अवसर भी पैदा करता है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र एवं महत्व (Scope and Importance of International Business)

I. अंतरराष्ट्रीय व्यापार की संकल्पना (Concept of International Business):

अंतरराष्ट्रीय व्यापार (International Business) से तात्पर्य है ऐसे व्यावसायिक गतिविधियों से जो दो या दो से अधिक देशों के बीच होती हैं। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, प्रौद्योगिकी तथा श्रम का आदान-प्रदान शामिल होता है।

II. अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्षेत्र (Scope of International Business):

अंतरराष्ट्रीय व्यापार का दायरा केवल माल और सेवाओं की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई विविध आयाम होते हैं:

1. वस्तुओं का आयात-निर्यात (Import & Export of Goods):

- ✓ अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे प्राथमिक रूप।
- ✓ जैसे भारत का अमेरिका को कपास का निर्यात।

2. सेवाओं का व्यापार (Trade in Services):

- ✓ बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, सूचना तकनीक, शिक्षा, आदि।
- ✓ जैसे भारत की IT कंपनियाँ अमेरिका के लिए सॉफ्टवेयर सेवाएँ प्रदान करती हैं।

3. विदेशी निवेश (Foreign Investment):

- ✓ एक देश की कंपनी का दूसरे देश में पूंजी निवेश करना।
- ✓ इसके दो रूप:
  - FDI (Foreign Direct Investment): जैसे – Amazon द्वारा भारत में गोदाम स्थापित करना।
  - FPI (Foreign Portfolio Investment): शेयर बाज़ार में निवेश।

4. प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण (Technology Transfer):

- ✓ एक देश से दूसरे देश में तकनीक का स्थानांतरण।
- ✓ जैसे – जापान की ऑटोमोबाइल तकनीक भारत में।

5. संविदात्मक निर्माण (Contract Manufacturing):

- ✓ एक कंपनी किसी विदेशी कंपनी को अपने लिए उत्पाद बनवाती है।
- ✓ जैसे – Nike अपने जूते चीन/भारत में बनवाती है।

6. फ्रेंचाइज़िंग और लाइसेंसिंग (Franchising & Licensing):

- ✓ स्थानीय फर्मों को ब्रांड, नाम, तकनीक का उपयोग करने की अनुमति देना।
- ✓ जैसे – McDonald's की फ्रेंचाइज़ भारत में।

7. मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) का संचालन:

- ✓ वे कंपनियाँ जो कई देशों में अपने प्लांट, कार्यालय और शाखाएँ संचालित करती हैं।

III. अंतरराष्ट्रीय व्यापार का महत्व (Importance of International Business):

1. विदेशी मुद्रा अर्जित करना (Earning Foreign Exchange):

- ✓ निर्यात के माध्यम से देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जो आयात और भुगतान संतुलन में सहायक होती है।

2. उद्योगों का विकास (Industrial Growth):

- ✓ बड़े बाजार की उपलब्धता के कारण कंपनियाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं, जिससे औद्योगीकरण को बल मिलता है।

3. **रोजगार के अवसर (Employment Generation):**
   - ✓ उत्पादन, परिवहन, निर्यात-आयात आदि से जुड़े कई रोजगार उत्पन्न होते हैं।
4. **नई तकनीक और नवाचार (Technology Transfer and Innovation):**
   - ✓ विदेशों से अत्याधुनिक तकनीक और कार्यप्रणालियाँ सीखने को मिलती हैं।
5. **उपभोक्ता की पसंद का विस्तार (Consumer Choice):**
   - ✓ उपभोक्ताओं को विदेशी उत्पाद भी उपलब्ध होते हैं, जिससे गुणवत्ता और विकल्प बढ़ते हैं।
6. **व्यापार संतुलन में सुधार (Balance of Trade):**
   - ✓ निर्यात बढ़ाकर देश अपने व्यापार घाटे को कम कर सकता है।
7. **राजनयिक और वैश्विक संबंध (International Relations):**
   - ✓ व्यापारिक रिश्तों के कारण देशों के बीच आपसी सहयोग, शांति और समझ बढ़ती है।
8. **मूल्य प्रतिस्पर्धा (Price Competition):**
   - ✓ अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है जिससे उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर और मूल्य उचित होता है।
9. **विकासशील देशों को अवसर (Opportunities for Developing Countries):**
   - ✓ वैश्विक मंच पर भागीदारी से विकासशील देश निवेश, तकनीक और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

उदाहरण (Examples):

- ➢ भारत द्वारा अमेरिका को दवाइयों का निर्यात → विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।
- ➢ Apple कंपनी का चीन में उत्पादन करना → सस्ता श्रम और बड़ी मात्रा में उत्पादन।
- ➢ Starbucks की भारत में फ्रेंचाइज़ी → ब्रांड विस्तार और स्थानीय साझेदारी।

निष्कर्ष (Conclusion):

- ➢ अंतरराष्ट्रीय व्यापार आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था का आधार है। यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास, रोजगार, नवाचार, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में अहम भूमिका निभाता है। इसके व्यापक क्षेत्र और महत्त्व के कारण यह व्यवसायों के लिए असीम अवसर प्रदान करता है।

ToppersNotes
Unleash the topper in you

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत (Theories of International Trade)

अर्थ (Meaning):

- ➢ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत यह बताते हैं कि दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार क्यों होता है, कैसे होता है, और किससे कौन-सा लाभ होता है। ये सिद्धांत व्यापार की दिशा, पैमाने, विशेषीकरण (specialization) और लाभ के वितरण को समझाने में सहायक होते हैं।
- ➢ **मुख्य सिद्धांत (Major Theories):**
- ➢ हम इन्हें दो भागों में बाँट सकते हैं:
  1. परंपरागत सिद्धांत (Classical Theories)
  2. आधुनिक सिद्धांत (Modern Theories)

I. **परंपरागत सिद्धांत (Classical Theories)**

1. **सार्थक अधिशेष सिद्धांत (Mercantilism Theory)**
   - ✓ 16वीं से 18वीं शताब्दी तक प्रभावी
   - ✓ देश को समृद्ध बनाने के लिए अधिक से अधिक निर्यात और कम से कम आयात करने की सलाह दी जाती थी।
   - ✓ Foreign exchange (सोना/चाँदी) जमा करने पर ज़ोर।
- ➢ **आलोचना:** यह सिद्धांत संरक्षणवादी है और दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाता है।

2. पूर्ण विशेषीकरण का सिद्धांत (Theory of Absolute Advantage)

- ✓ प्रस्तावक: Adam Smith (1776)
- ✓ किसी देश को उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिसमें उसे अन्य देश की तुलना में पूर्ण लाभ (Absolute Advantage) हो यानी वह वस्तु कम संसाधन/कम लागत में बना सके।

उदाहरण:

- ➢ भारत → वस्त्र में श्रेष्ठ
- ➢ अमेरिका → मशीन में श्रेष्ठ
- ➢ → भारत वस्त्र बनाए, अमेरिका मशीन → दोनों को लाभ

3. तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत (Theory of Comparative Advantage)

- ✓ प्रस्तावक: David Ricardo (1817)
- ✓ भले ही एक देश हर वस्तु में बेहतर हो, फिर भी उसे उस वस्तु में विशेषीकरण करना चाहिए जिसमें तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ हो।

मुख्य बिंदु:

- ➢ अवसर लागत (Opportunity Cost) के आधार पर व्यापार का निर्णय
- ➢ सभी देश व्यापार से लाभ उठा सकते हैं

4. सापेक्ष लागत का सिद्धांत (Opportunity Cost Theory)

- ✓ **प्रस्तावक: Haberler**
- ✓ Ricardo के तुलनात्मक लाभ सिद्धांत को आधुनिक रूप देना
- ✓ यह सिद्धांत उत्पादन के सभी संसाधनों को ध्यान में रखता है (मजदूर, पूंजी, भूमि आदि)
- ✓ उत्पादन संभाव्यता वक्र (Production Possibility Curve) का उपयोग करता है

II. आधुनिक सिद्धांत (Modern Theories)

5. हैक्सचर-ओहली सिद्धांत (Heckscher-Ohlin Theory)

- ✓ प्रस्तावक: Eli Heckscher & Bertil Ohlin
- ✓ इसे Factor Endowment Theory भी कहा जाता है।
- ✓ प्रत्येक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनके उत्पादन हेतु संसाधन (Factors of Production) उसके पास प्रचुर मात्रा में हैं।
- ✓ अन्य वस्तुएँ वह आयात करेगा जिनके संसाधन उसके पास सीमित हैं।

उदाहरण:

- ➢ भारत (श्रम अधिक) → श्रम-प्रधान वस्तुएँ
- ➢ जर्मनी (पूंजी अधिक) → पूंजी-प्रधान वस्तुएँ

6. लेंटिफ पैराडॉक्स (Leontief Paradox)

- ✓ प्रस्तावक: Wassily Leontief (1953)
- ✓ अमेरिका, जो पूंजी-समृद्ध देश है, फिर भी वह श्रम-प्रधान वस्तुओं का निर्यात कर रहा था।
- ✓ यह Hackser-Ohlin सिद्धांत के विरुद्ध था।
- ✓ **निष्कर्ष:** व्यापार व्यवहार में सिर्फ संसाधन प्रचुरता नहीं, बल्कि तकनीक, उत्पादकता और मांग भी महत्त्वपूर्ण होती है।

7. **सामाजिक लागत-लाभ सिद्धांत (Theory of International Cost Differences)**
    - ✓ देश उत्पादन की लागत और तकनीकी कुशलता के आधार पर व्यापार करते हैं।
8. **उत्पाद जीवन चक्र सिद्धांत (Product Life Cycle Theory)**
    - ✓ प्रस्तावक: Raymond Vernon
    - ✓ एक उत्पाद का अंतरराष्ट्रीय व्यापार में चलन उसके जीवन चक्र के चरण पर निर्भर करता है:
        - परिचय (Introduction) → नवाचार देश
        - वृद्धि (Growth) → निर्यात
        - परिपक्वता (Maturity) → विदेशी उत्पादन शुरू
        - अवसान (Decline) → घरेलू उत्पादन कम, आयात अधिक
9. **स्वांगत व्यापार सिद्धांत (Intra-Industry Trade Theory)**
    - ✓ यह बताता है कि देश एक ही उद्योग की समान वस्तुओं का आयात और निर्यात दोनों कर सकते हैं।
    - ✓ जैसे – भारत जर्मनी से कार आयात करता है और जापान को कार निर्यात करता है।

तुलना तालिका (Comparison Table):

सिद्धांत	**प्रस्तावक**	**मुख्य विचार**
Mercantilism	Thomas Mun आदि	अधिक निर्यात, कम आयात
Absolute Advantage	Adam Smith	पूर्ण लाभ वाली वस्तु का निर्यात
Comparative Advantage	David Ricardo	तुलनात्मक लाभ पर आधारित
Factor Endowment	Heckscher-Ohlin	संसाधन प्रचुरता पर आधारित
Leontief Paradox	Wassily Leontief	HO सिद्धांत का विरोधाभास
Product Life Cycle	Vernon	व्यापार उत्पाद के जीवन चक्र पर आधारित

निष्कर्ष (Conclusion):

- ➢ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि:
    - ✓ देश व्यापार क्यों करते हैं?
    - ✓ वे किन वस्तुओं का निर्यात या आयात करेंगे?
    - ✓ संसाधनों, लागत, तकनीक और लाभ का व्यापार में क्या प्रभाव है?
- ➢ ये सिद्धांत वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विकासशील देशों की रणनीति, और विदेशी व्यापार नीति बनाने में अत्यंत सहायक होते हैं।

<u>विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI)</u>

I. **विदेशी निवेश की संकल्पना (Concept of Foreign Investment):**

विदेशी निवेश (Foreign Investment) वह प्रक्रिया है जिसमें कोई विदेशी व्यक्ति, संस्था या कंपनी किसी दूसरे देश की कंपनी या परिसंपत्ति में निवेश करती है। इसका उद्देश्य लाभ अर्जित करना, बाजार में प्रवेश करना, या वैश्विक व्यापार विस्तार करना होता है।

विदेशी निवेश दो प्रमुख रूपों में होता है:

1. FDI – Foreign Direct Investment (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश)
2. FPI – Foreign Portfolio Investment (विदेशी पोर्टफोलियो निवेश)

II. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI – Foreign Direct Investment)

परिभाषा:

- जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश में स्थायी रूप से व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से पूंजी, तकनीक या प्रबंधन के रूप में निवेश करती है, तो उसे FDI कहा जाता है।
- इसमें निवेशक को कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण (Management Control) और स्थायी हित प्राप्त होता है।

मुख्य विशेषताएँ:

बिंदु	**विवरण**
नियंत्रण	निवेशक को कंपनी में निर्णय लेने का अधिकार होता है
स्वरूप	इक्विटी शेयर, संयंत्र निर्माण, संयोजन, टेकओवर
अवधि	दीर्घकालिक (Long-term)
निवेश का लक्ष्य	उत्पादन, व्यापार संचालन
जोखिम	अपेक्षाकृत अधिक

FDI के प्रकार:

1. ग्रीनफील्ड निवेश (Greenfield Investment):

- ✓ नया संयंत्र/कारखाना खड़ा करना
- ✓ जैसे – Hyundai द्वारा भारत में प्लांट बनाना

2. ब्राउनफील्ड निवेश (Brownfield Investment):

- ✓ मौजूदा कंपनी का अधिग्रहण
- ✓ जैसे – Walmart द्वारा Flipkart में निवेश

III. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI – Foreign Portfolio Investment)

परिभाषा:

- जब कोई विदेशी निवेशक किसी देश के शेयर बाज़ार, बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियाँ (Securities) आदि में लघु अवधि के लाभ हेतु निवेश करता है, तो उसे FPI कहा जाता है।
- इसमें निवेशक को कंपनी में कोई प्रबंधन नियंत्रण नहीं होता।

मुख्य विशेषताएँ:

बिंदु	**विवरण**
नियंत्रण	निवेशक का कंपनी प्रबंधन में कोई दखल नहीं
स्वरूप	शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर, सरकारी प्रतिभूतियाँ
अवधि	अल्पकालिक (Short-term)
निवेश का लक्ष्य	पूंजी लाभ, ब्याज आय
जोखिम	अधिक अस्थिर (Volatile)

IV. FDI और FPI में अंतर (Difference between FDI and FPI)

आधार	**FDI**	**FPI**
स्वामित्व	प्रत्यक्ष नियंत्रण और स्वामित्व	केवल वित्तीय निवेश
अवधि	दीर्घकालिक	अल्पकालिक

जोखिम	कम	अधिक (बाजार आधारित)
उदाहरण	Amazon का भारत में गोदाम खोलना	विदेशी निवेशकों द्वारा Sensex में निवेश
रूप	प्लांट, इक्विटी, टेक्नोलॉजी	शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर
स्थायित्व	स्थिर और टिकाऊ	अस्थिर और संवेदनशील
मुनाफा	लाभांश + नियंत्रण	पूंजी लाभ/ब्याज

V. भारत में FDI और FPI का महत्व (Importance of FDI & FPI in India):

FDI के लाभ:

1. तकनीकी विकास और नवाचार
2. रोजगार सृजन
3. निर्यात में वृद्धि
4. बुनियादी ढाँचा विकास
5. विदेशी मुद्रा का प्रवाह

FPI के लाभ:

1. शेयर बाजार की तरलता में वृद्धि
2. विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि
3. घरेलू निवेशकों के लिए बाजार का विकास
4. वित्तीय गहराई (Financial Deepening)

VI. भारत में नियामक संस्थाएँ (Regulatory Bodies):

निवेश	**नियामक**
FDI	DPIIT (वाणिज्य मंत्रालय), RBI, FEMA कानून
FPI	SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड), RBI

VII. FDI के क्षेत्र (Sectors for FDI):

भारत में FDI दो मार्गों से आता है:

1. **स्वचालित मार्ग (Automatic Route):**
   - ✓ सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं
   - ✓ जैसे – मैन्युफैक्चरिंग, खनन, ई-कॉमर्स (कुछ शर्तों के साथ)
2. **सरकारी मार्ग (Government Route):**
   - ✓ सरकार की अनुमति आवश्यक होती है
   - ✓ जैसे – रक्षा, मीडिया, मल्टी-ब्रांड रिटेल

निष्कर्ष (Conclusion):

- ➢ FDI और FPI दोनों विदेशी निवेश के रूप हैं, लेकिन इनके प्रभाव, नियंत्रण, अवधि और उद्देश्य भिन्न होते हैं।
- ➢ भारत जैसे विकासशील देशों के लिए FDI दीर्घकालिक आर्थिक विकास में सहायक है, जबकि FPI अल्पकालिक पूंजी प्रवाह और वित्तीय बाजार की तरलता में सहायक होता है।

अंतरराष्ट्रीय भुगतान संतुलन (Balance of Payments - BoP)

I. परिभाषा (Definition):

Balance of Payments (BoP) एक वित्तीय विवरण (Financial Statement) है जो किसी देश के एक निश्चित अवधि (आमतः एक वर्ष) के दौरान अन्य देशों के साथ किए गए सभी आर्थिक लेन-देन को रिकॉर्ड करता है।

- यह दर्शाता है कि किसी देश ने विदेशी मुद्रा कहाँ से अर्जित की (आगम) और कहाँ खर्च की (व्यय)।

II. प्रमुख उद्देश्य (Objectives of BoP):

1. देश की विदेशी मुद्रा स्थिति जानना
2. अंतरराष्ट्रीय व्यापार और पूंजी प्रवाह का विश्लेषण करना
3. वित्तीय नीति और विनिमय दर तय करने में मदद
4. व्यापार घाटा या अधिशेष का मूल्यांकन

III. भुगतान संतुलन की संरचना (Structure of BoP):

- BoP को मुख्यतः दो प्रमुख खातों में विभाजित किया जाता है:

1. चालू खाता (Current Account)

- इसमें माल और सेवाओं का व्यापार, एकतरफा हस्तांतरण, और आय को शामिल किया जाता है।

उप-खण्ड	विवरण
➢ माल का व्यापार (Merchandise Trade)	निर्यात - आयात (Visible items)
➢ सेवाओं का व्यापार (Invisibles)	Banking, IT, Tourism, Shipping
➢ आय (Income)	विदेशी निवेश से लाभ/ब्याज
➢ एकतरफा स्थानांतरण (Transfers)	अनुदान, रेमिटेंस, सहायता (Remittances from NRIs etc.)

- यदि निर्यात > आयात = चालू खाता अधिशेष
- यदि आयात > निर्यात = चालू खाता घाटा

2. पूंजी खाता (Capital Account)

- इसमें लंबी व छोटी अवधि के वित्तीय निवेश को रिकॉर्ड किया जाता है।

उप-खण्ड	विवरण
➢ FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश)	लंबी अवधि का निवेश
➢ FPI (पोर्टफोलियो निवेश)	अल्पकालिक निवेश
➢ बाहरी वाणिज्यिक ऋण (External Commercial Borrowings)	भारत द्वारा विदेशी ऋण
➢ NRI जमा (NRI Deposits)	अनिवासी भारतीयों द्वारा बैंक जमा
➢ RBI के मुद्रा भंडार में परिवर्तन	विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि/कमी

पूरक खाते (Errors and Omissions):

- यह खंड अनजान त्रुटियों, छिपे लेन-देन या रिकॉर्डिंग की विसंगतियों को दर्शाता है जिससे BoP को संतुलन में रखा जा सके।

IV. BoP का संतुलन और असंतुलन (BoP Surplus and Deficit):

संतुलन (Equilibrium):

- जब कुल प्राप्तियाँ = कुल व्यय, तो BoP संतुलन में होता है।

असंतुलन (Disequilibrium):

- जब कुल प्राप्तियाँ ≠ कुल व्यय, तो असंतुलन होता है।
- विशेषतः जब चालू खाता घाटा हो और पूंजी प्रवाह से उसकी पूर्ति न हो पाए।

V. असंतुलन के कारण (Causes of Disequilibrium in BoP):

1. अत्यधिक आयात
2. निर्यात में गिरावट
3. तेल कीमतों में वृद्धि (OPEC Effect)
4. कम विदेशी निवेश प्रवाह
5. ऋण चुकौती और ब्याज भुगतान
6. अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की कमी
7. अस्थिर राजनीतिक-आर्थिक स्थितियाँ

VI. असंतुलन दूर करने के उपाय (Corrective Measures):

1. मुद्रा अवमूल्यन (Devaluation)
2. निर्यात प्रोत्साहन नीतियाँ
3. आयात प्रतिबंध/शुल्क वृद्धि
4. विदेशी निवेश आकर्षित करना (FDI/FPI)
5. RBI द्वारा मौद्रिक नीति समायोजन

VII. भारत में BOP की स्थिति (India's BoP Snapshot):

(डेटा उदाहरणात्मक)

वर्ष	चालू खाता घाटा	पूंजी खाता	कुल BoP
2022-23	$35 बिलियन	$60 बिलियन	$25 बिलियन अधिशेष
2023-24	$50 बिलियन	$55 बिलियन	$5 बिलियन अधिशेष

- भारत प्रायः चालू खाता घाटे वाला देश है, जिसे FDI/FPI द्वारा संतुलित किया जाता है।

VIII. चालू खाता बनाम पूंजी खाता (Current vs. Capital Account)

आधार	चालू खाता	पूंजी खाता
प्रकृति	व्यापार और आय	निवेश और ऋण
अवधि	अल्पकालिक	दीर्घकालिक
स्थिरता	अधिक अस्थिर	तुलनात्मक रूप से स्थिर
संतुलन का प्रभाव	सीधा आर्थिक विकास पर	मुद्रा भंडार पर असर

निष्कर्ष (Conclusion):

- BoP किसी देश की अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शक्ति और विदेशी मुद्रा स्थिति को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण संकेतक है। इसकी निगरानी से आर्थिक नीतियाँ, मुद्रा विनिमय दर, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सही दिशा दी जा सकती है।

क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण (Regional Economic Integration)

I. परिचय (Introduction):

- क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से तात्पर्य है दो या दो से अधिक देशों के बीच इस प्रकार की साझेदारी, जिसमें वे अपने बीच व्यापार, निवेश, सेवाएँ, श्रमिकों और पूंजी के प्रवाह को सरल, मुक्त और बाधारहित बनाने के लिए संयुक्त आर्थिक समझौतों में प्रवेश करते हैं।
- **उद्देश्य:**
  - ✓ क्षेत्रीय देशों के बीच आर्थिक सहयोग,
  - ✓ व्यापारिक बाधाओं को समाप्त करना,
  - ✓ सामूहिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।

II. परिभाषा (Definition):

- जब एक ही भौगोलिक क्षेत्र के देश आपसी व्यापार, पूंजी और श्रमिकों के प्रवाह पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए एकजुट होते हैं, तो उसे क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण कहते हैं।

III.क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रकार (Types of Regional Economic Integration):

- इसे 5 स्तरों में वर्गीकृत किया गया है (क्रमशः बढ़ती गहराई के अनुसार):

स्तर	नाम	विवरण
1	व्यापार क्षेत्र (Free Trade Area)	सदस्य देश आपसी व्यापार पर शुल्क/कोटा हटाते हैं (जैसे NAFTA, SAFTA)
2	कस्टम यूनियन (Customs Union)	व्यापार क्षेत्र + सभी देशों द्वारा बाहरी देशों पर समान शुल्क लगाना
3	साझा बाजार (Common Market)	कस्टम यूनियन + पूंजी और श्रमिकों की स्वतंत्र आवाजाही (जैसे EU)
4	आर्थिक संघ (Economic Union)	साझा बाजार + साझा आर्थिक/मौद्रिक नीति
5	राजनीतिक संघ (Political Union)	आर्थिक संघ + राजनीतिक एकता (जैसे US 50 states)

IV.प्रमुख उदाहरण (Examples of Regional Integration):

संगठन	क्षेत्र	स्वरूप
EU (European Union)	यूरोप	आर्थिक + मौद्रिक + साझा बाज़ार
ASEAN	दक्षिण-पूर्व एशिया	व्यापार और आर्थिक सहयोग
NAFTA (अब USMCA)	अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको	मुक्त व्यापार क्षेत्र
SAARC / SAFTA	दक्षिण एशिया	व्यापार सहयोग
MERCOSUR	दक्षिण अमेरिका	कस्टम यूनियन

V. क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लाभ (Benefits):

1. व्यापार में वृद्धि – सदस्य देशों के बीच शुल्क-मुक्त व्यापार बढ़ता है
2. मूल्य में प्रतिस्पर्धा – उपभोक्ताओं को सस्ते और बेहतर विकल्प मिलते हैं
3. निवेश आकर्षित होता है – कंपनियाँ बड़े क्षेत्रीय बाज़ार तक पहुँच बना पाती हैं
4. रोजगार के अवसर – व्यवसायों के विस्तार से नौकरियाँ बढ़ती हैं
5. राजनीतिक स्थिरता – सदस्य देशों के बीच सहयोग से टकराव की संभावना कम होती है
6. प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान – विकसित देश विकासशील देशों को सहयोग देते हैं

VI. क्षेत्रीय एकीकरण की चुनौतियाँ (Challenges):

1. राजनीतिक मतभेद – सदस्य देशों के हित टकरा सकते हैं
2. छोटे देशों पर प्रभाव – बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ हावी हो सकती हैं
3. राष्ट्रीय संप्रभुता में कमी – नीति निर्धारण में स्वतंत्रता घटती है
4. असमान विकास – सभी देश समान रूप से लाभान्वित नहीं होते
5. भीतरू प्रतिस्पर्धा – घरेलू उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित हो सकते हैं

VII. भारत और क्षेत्रीय एकीकरण (India & Regional Integration):

➢ भारत निम्न संगठनों का सदस्य है:

संगठन	**भूमिका**
SAFTA	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAARC के तहत)
ASEAN FTA	भारत और ASEAN देशों के बीच व्यापार समझौता
BIMSTEC	बंगाल की खाड़ी क्षेत्रीय सहयोग समूह
IBSA	भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग

➢ भारत RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) से बाहर रहा।

VIII. क्षेत्रीय बनाम वैश्विक एकीकरण (Regional vs. Global Integration)

पहलू	**क्षेत्रीय (Regional)**	**वैश्विक (Global)**
दायरा	सीमित (स्थानीय क्षेत्र)	वैश्विक (सभी देश)
उदाहरण	EU, SAFTA	WTO, IMF
नियंत्रण	सदस्य देशों द्वारा	वैश्विक संगठन द्वारा
गति	अधिक	धीमी

निष्कर्ष (Conclusion):

➢ क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण वैश्विक व्यापार के युग में एक मजबूत रणनीति बन चुका है। यह न केवल आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देता है, बल्कि सदस्य देशों के बीच राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक मेल-जोल, और स्थायी विकास को भी प्रोत्साहित करता है।

➢ हालाँकि, इसके लिए मजबूत नीतिगत समन्वय, समानता की भावना, और राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है।

4 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ (4 Major International Economic Institutions)

परिचय (Introduction):

➢ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएँ वे वैश्विक संगठन हैं जो देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, वित्तीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। ये संस्थाएँ विकासशील देशों को सहायता, ऋण, और तकनीकी समर्थन भी प्रदान करती हैं।

I. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF – International Monetary Fund)

विवरण	**जानकारी**
स्थापना	1944 (ब्रेटन वुड्स सम्मेलन)
मुख्यालय	वाशिंगटन डी.सी., USA
सदस्य देश	190+ (भारत भी संस्थापक सदस्य)

➢ **मुख्य उद्देश्य:**

1. वैश्विक विनिमय दरों की स्थिरता बनाए रखना
2. विदेशी मुद्रा संकट से देशों को बचाना
3. संघटन सदस्यों को अल्पकालिक ऋण देना
4. भुगतान संतुलन (BoP) सुधारने में सहायता

➢ **प्रमुख कार्य:**

✓ सदस्य देशों को IMF कोटा के आधार पर सहायता देना
✓ SDR (Special Drawing Rights) का वितरण
✓ वैश्विक वित्तीय रिपोर्टें: World Economic Outlook

विश्व बैंक समूह (World Bank Group)

विवरण	**जानकारी**
स्थापना	1944 (IMF के साथ)
मुख्यालय	वाशिंगटन डी.सी., USA
मुख्य संस्था	IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)

➢ **अन्य घटक संस्थाएँ:**

1. IBRD – पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु ऋण
2. IDA – अत्यंत गरीब देशों को रियायती ऋण
3. IFC – निजी क्षेत्र में निवेश
4. MIGA – राजनीतिक जोखिम बीमा
5. ICSID – निवेश विवाद निपटान

➢ **मुख्य उद्देश्य:**

1. विकासशील देशों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना
2. गरीबी उन्मूलन और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास
3. शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, जल प्रबंधन आदि क्षेत्रों में परियोजनाएँ

➢ भारत को कई बड़े परियोजनाओं में विश्व बैंक से ऋण मिला है – जैसे ग्रामीण सड़क योजना, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत।

III.विश्व व्यापार संगठन (WTO – World Trade Organization)

विवरण	**जानकारी**
स्थापना	1 जनवरी 1995 (GATT का उत्तराधिकारी)
मुख्यालय	जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
सदस्य	164+ देश (भारत सदस्य है)

➢ **मुख्य उद्देश्य:**

1. वैश्विक व्यापार को स्वतंत्र, निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाना
2. टैरिफ और व्यापार बाधाओं को कम करना
3. व्यापार विवादों को सुलझाना
4. विकासशील देशों को व्यापार में भागीदारी का अवसर देना

- **मुख्य समझौते:**
  - ✓ GATT (माल का व्यापार)
  - ✓ GATS (सेवाओं का व्यापार)
  - ✓ TRIPS (बौद्धिक संपदा अधिकार)
- WTO के अधीन भारत ने कई विवादों में भाग लिया (जैसे: कृषि सब्सिडी, IT निर्यात विवाद आदि)।
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development)

विवरण	**जानकारी**
स्थापना	1964
मुख्यालय	जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
उद्देश्य	व्यापार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना

मुख्य उद्देश्य:

1. विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार में मदद करना
2. विनिर्माण, निर्यात, निवेश को बढ़ाना
3. नीतिगत शोध और डेटा विश्लेषण
4. E-commerce, डिजिटल इकॉनॉमी में सलाह और मार्गदर्शन

प्रकाशित रिपोर्ट:

- Trade and Development Report
- World Investment Report
- Technology and Innovation Report
- UNCTAD विकासशील देशों को WTO और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में न्यायपूर्ण भागीदारी दिलाने की वकालत करता है।

तुलनात्मक सारणी (Comparative Table):

संस्था	**स्थापना**	**मुख्य कार्य**	**मुख्यालय**
IMF	1944	मुद्रा स्थिरता, अल्पकालिक ऋण	वाशिंगटन डीसी
World Bank	1944	दीर्घकालिक ऋण, विकास	वाशिंगटन डीसी
WTO	1995	वैश्विक व्यापार नियम	जिनेवा
UNCTAD	1964	विकासशील देशों की व्यापार मदद	जिनेवा

निष्कर्ष (Conclusion):

- ये चारों संस्थाएँ वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ हैं। ये:
  - ✓ वित्तीय स्थिरता बनाए रखती हैं (IMF)
  - ✓ विकास को गति देती हैं (World Bank)
  - ✓ निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करती हैं (WTO)
  - ✓ विकासशील देशों की आवाज़ को सामने लाती हैं (UNCTAD)
- इनके सहयोग से वैश्विक आर्थिक संतुलन, साझेदारी, और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO - World Trade Organization)

परिचय (Introduction):

➤ विश्व व्यापार संगठन (WTO) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो वैश्विक व्यापार को नियमित, नियंत्रित और सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, और पारदर्शी अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को प्रोत्साहित करना है।

स्थापना (Establishment):

बिंदु	विवरण
स्थापना तिथि	1 जनवरी 1995
पूर्ववर्ती संस्था	GATT (General Agreement on Tariffs and Trade – 1948)
मुख्यालय	जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
सदस्य देश	164+ (भारत संस्थापक सदस्य है)
आधिकारिक भाषाएँ	अंग्रेज़ी, फ्रेंच, स्पेनिश

उद्देश्य (Objectives of WTO):

1. वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करना
2. व्यापार बाधाओं को कम करना (टैरिफ, कोटा, सब्सिडी आदि)
3. व्यापार विवादों का निपटारा करना
4. सदस्य देशों को नीति निर्माण में पारदर्शिता प्रदान करना
5. विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार में भागीदारी के लिए समर्थन देना

WTO के प्रमुख कार्य (Major Functions of WTO):

कार्य	विवरण
1	वैश्विक व्यापार के नियमों का निर्माण और निगरानी
2	व्यापार विवादों को सुलझाना (Dispute Settlement Mechanism)
3	व्यापार नीतियों की समीक्षा करना (Trade Policy Review)
4	GATT, GATS, TRIPS जैसे समझौतों को लागू करना
5	विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण देना

WTO के प्रमुख समझौते (Major Agreements under WTO):

समझौता	विवरण
GATT	माल के व्यापार पर समझौता (टैरिफ, कोटा)
GATS	सेवाओं के व्यापार पर समझौता (Banking, Tourism, IT etc.)
TRIPS	बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) – Patents, Copyrights
AOA (Agreement on Agriculture)	कृषि व्यापार का उदारीकरण
TBT (Technical Barriers to Trade)	मानकों और प्रमाणनों पर नियम
SPS (Sanitary & Phytosanitary Measures)	खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक

WTO की संरचना (Organizational Structure):

स्तर	इकाई
Ministerial Conference	सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था (हर 2 साल में बैठक)
General Council	दैनिक प्रशासनिक कार्य देखता है
Dispute Settlement Body	विवाद समाधान करता है
Trade Policy Review Body	व्यापार नीति की समीक्षा करता है
Committees	विशेष मुद्दों (IPR, कृषि, पर्यावरण) पर कार्य करते हैं

WTO और भारत (WTO and India):

भारत की भूमिका:

- भारत WTO का संस्थापक सदस्य है।
- भारत विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करता है।
- भारत ने WTO में कई विवादों में भाग लिया:
  - ✓ अमेरिका बनाम भारत – पोल्ट्री आयात विवाद
  - ✓ भारत बनाम अमेरिका – सोलर पैनल सब्सिडी विवाद

भारत की प्राथमिकताएँ:

- कृषि सब्सिडी की रक्षा
- बौद्धिक संपदा पर लचीलापन
- स्वदेशी उद्योगों का संरक्षण
- सेवा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाना

WTO की आलोचनाएँ (Criticism of WTO):

मुद्दा
विकासशील देशों के हितों की उपेक्षा
अमेरिका, यूरोप जैसे विकसित देशों का वर्चस्व
कृषि और IPR नियमों में असमानता
पर्यावरण और श्रमिक अधिकारों की अनदेखी
विवाद समाधान प्रक्रिया धीमी और जटिल

IX. वर्तमान स्थिति एवं सुधार (Recent Developments & Reforms):

- Appellate Body (Dispute Settlement का अंतिम स्तर) कई वर्षों से अकार्यशील है क्योंकि अमेरिका ने नए सदस्य नियुक्त नहीं किए।
- E-commerce, डिजिटल टैक्स, जलवायु व्यापार जैसे नए मुद्दों पर चर्चा जारी है।
- भारत बहुपक्षीय की बजाय बहु-देशीय (Plurilateral) समझौतों का विरोध करता है।

WTO बनाम GATT तुलना तालिका:

आधार	GATT	WTO
स्थापना	1948	1995
प्रकृति	समझौता (Agreement)	संगठन (Organization)

कार्यक्षेत्र	केवल वस्तुएँ	वस्तुएँ + सेवाएँ + IPR
बाध्यता	ढीली	कानूनी बाध्यकारी
विवाद समाधान	अस्थायी	संगठित प्रणाली (DSB)

निष्कर्ष (Conclusion):

- WTO एक ऐसा मंच है जो विश्व व्यापार को न्यायसंगत, खुला और पारदर्शी बनाने में सहायक है। हालाँकि इसे विकासशील देशों की आवश्यकताओं और वैश्विक न्याय को ध्यान में रखते हुए सुधारों की आवश्यकता है।
- भारत जैसे देशों के लिए WTO की नीति-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी अत्यंत आवश्यक है ताकि वे वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा और लाभ दोनों प्राप्त कर सकें।

मौद्रिक नीति (Monetary Policy)

परिभाषा (Definition):

- मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके माध्यम से देश का केंद्रीय बैंक (भारत में RBI) मुद्रा आपूर्ति (money supply) और ब्याज दरों (interest rates) को नियंत्रित करता है ताकि आर्थिक स्थिरता, महंगाई नियंत्रण, और आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
- मौद्रिक नीति बनाने वाला संस्थान:
  - ✓ भारत में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) मौद्रिक नीति का निर्माण और कार्यान्वयन करता है।
  - ✓ मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) इसका निर्णय लेती है।
- उद्देश्य (Objectives of Monetary Policy):

उद्देश्य	विवरण
महंगाई पर नियंत्रण	मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करके
आर्थिक विकास को बढ़ावा	उद्योगों को ऋण सस्ता उपलब्ध कराकर
मुद्रा का स्थायित्व	मुद्रा के मूल्य को स्थिर बनाए रखना
बेरोजगारी में कमी	निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन देकर
भुगतान संतुलन में सुधार	आयात-निर्यात के अंतर को संतुलित करना

मौद्रिक नीति के प्रकार (Types):

प्रकार	विवरण
तानाशाही (Tight / Contractionary)	जब महंगाई अधिक हो, तो मुद्रा की आपूर्ति घटाकर
उदार (Easy / Expansionary)	जब मंदी या बेरोजगारी हो, तो ऋण सस्ता कर मुद्रा बढ़ाकर

मौद्रिक नीति के प्रमुख साधन (Instruments of Monetary Policy):

A. मात्रात्मक उपाय (Quantitative Measures):

- ये उपाय मुद्रा की कुल मात्रा को प्रभावित करते हैं।

उपाय	विवरण
रेपो रेट (Repo Rate)	वह दर जिस पर RBI बैंकों को ऋण देता है
रिवर्स रेपो रेट (Reverse Repo Rate)	वह दर जिस पर RBI बैंकों से धन स्वीकार करता है
बैंक दर (Bank Rate)	RBI द्वारा दीर्घकालिक ऋण पर ली जाने वाली दर

CRR (Cash Reserve Ratio)	बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा RBI के पास नकद रखना होता है
SLR (Statutory Liquidity Ratio)	बैंकों को अपनी जमा राशि का एक भाग सोना/बॉन्ड में रखना होता है
ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO)	RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदना या बेचना

B. गुणात्मक उपाय (Qualitative Measures):

- ये उपाय ऋण की दिशा और उद्देश्य को नियंत्रित करते हैं।

उपाय	विवरण
ऋण सीमाएँ (Margin Requirements)	ऋण पर अधिक मार्जिन रखना
ऋण की दिशा निर्देशित करना	प्राथमिक क्षेत्र/कृषि/लघु उद्योगों को प्राथमिकता देना
नैतिक दबाव (Moral Suasion)	बैंकों को परामर्श देकर नियंत्रित करना
प्रत्यक्ष नियंत्रण	दिशानिर्देश जारी कर नियंत्रण करना

मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC):

- यह एक 6-सदस्यीय समिति होती है।
- इसका कार्य है रेपो रेट को तय करना।
- हर दो माह (bi-monthly) में बैठक होती है।
- RBI गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं।
- एक संतुलित मौद्रिक नीति किसी भी अर्थव्यवस्था के स्थायित्व, विकास, और मूल्य नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक होती है।
- RBI द्वारा उचित मौद्रिक नीति से मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, और विकास के बीच संतुलन बना रहता है।

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

परिभाषा (Definition):

- राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने आय (Revenue) और व्यय (Expenditure) को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है।
- यह नीति सरकार द्वारा करों, उधार, और सरकारी खर्च के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है।

उद्देश्य (Objectives of Fiscal Policy):

उद्देश्य	विवरण
आर्थिक स्थिरता	मुद्रास्फीति और मंदी को नियंत्रित करना
आर्थिक विकास	अवसंरचना, उद्योग और कृषि को बढ़ावा देना
बेरोजगारी में कमी	रोजगार सृजन के लिए योजनाएँ और निवेश
आय वितरण में समानता	गरीबों को सब्सिडी, शिक्षा, स्वास्थ्य
संसाधनों का कुशल उपयोग	सरकारी खर्च के माध्यम से उत्पादक निवेश

राजकोषीय नीति के प्रकार (Types of Fiscal Policy):

प्रकार	उद्देश्य
विस्तारित नीति (Expansionary)	आर्थिक मंदी के समय, खर्च बढ़ाना और कर घटाना
संकुचनात्मक नीति (Contractionary)	महंगाई के समय, खर्च घटाना और कर बढ़ाना